

एनएलएसआईयू, बेंगलुरु

परियोजना: 'डिजिटल कानूनी साक्षरता-प्रसार और मूल्यांकन'

महत्वपूर्ण पहल:

- कानूनी साक्षरता के लिए समर्पित YouTube चैनल CEERA-NLISU-DoJ की डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करें
- प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना
- राष्ट्रीय स्तर पर लीगल एड कम्पटीशन का आयोजन
- कानूनी साक्षरता के लिए पिक्चर बुक का प्रकाशन

आउटरीच: 3,983

Website : www.nls.ac.in/



ग्रामीण विकास के राज्य संस्थान

एसआईआरडी, पुणे, महाराष्ट्र

परियोजना: 'महाराष्ट्र में राज्य की 100 ग्राम पंचायतों में विधि दूतों का प्रचार'

महत्वपूर्ण पहल:

- ग्राम स्तर पर 700 विधिवृत्तों की पहचान और क्षमता निर्माण
- YASHADA के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कानूनी साक्षरता सामग्री और उपकरण का निर्माण

आउटरीच: 519

Website : www.yashada.org/



बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (BIPARD), पटना

परियोजना: 'बिहार की ग्राम पंचायतों में 700 विधि मित्रों का प्रचार'

महत्वपूर्ण पहल:

- 700 विधि मित्रों का क्षमता निर्माण
- आईईसी सामग्री और सेवाप्रदाता प्रशिक्षण किट विकसित करना

आउटरीच: 454

Website : www.bipard.bihar.gov.in/



अब्दुल नज़ीर साहब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायत राज, मैसूर, कर्नाटक

परियोजना: 'मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार'

महत्वपूर्ण पहल:

- पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण सत्रों का वीडियो/प्रिंट प्रलेखन सुनिश्चित करें
- आईईसी किट और प्रशिक्षण मैनुअल विकसित करें

आउटरीच: 31,468

Website : www.sirdmysuru.karnataka.gov.in/



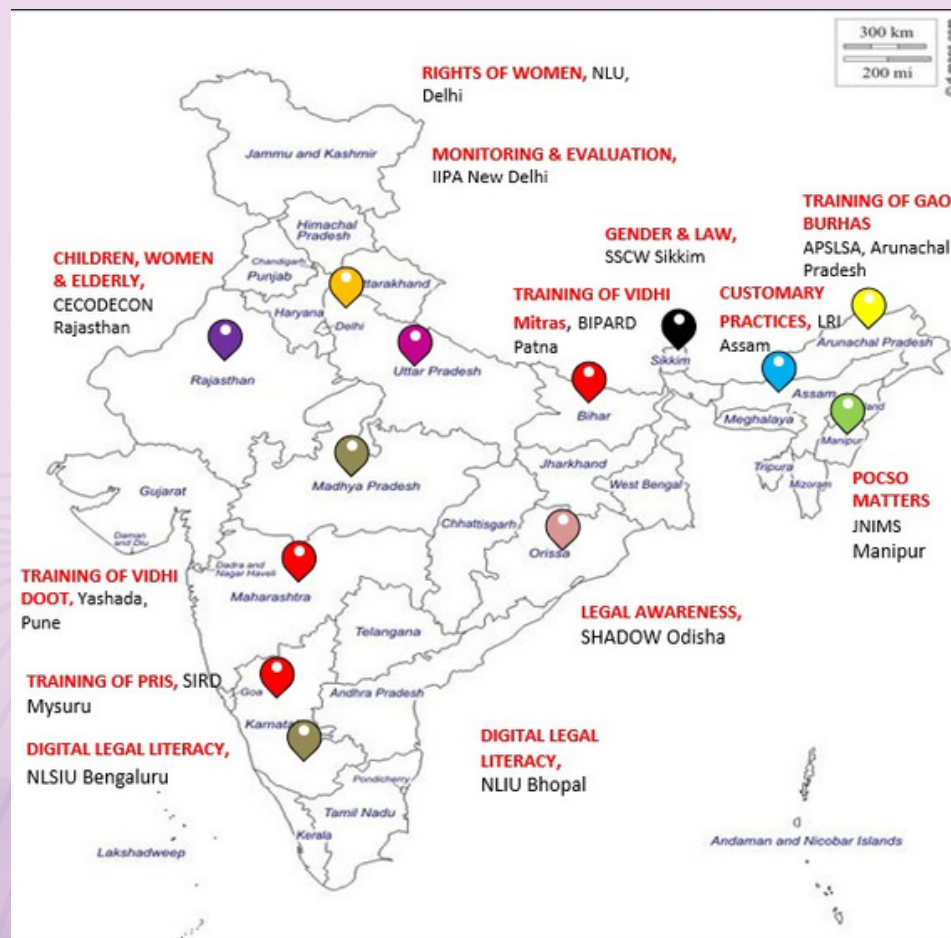
मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिलांग, मेघालय

परियोजना: 'सामुदायिक मध्यस्थता'

Website : www.mslsa.gov.in/



हमारे 14 भागीदार: प्रभाव क्षेत्र



प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (दिशा)

एक्सेस टू जस्टिस डिवीज़न,

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस

मानसिंह रोड, जैसलमेर हाउस

नई दिल्ली - 110011

Ph: 011-23072147, Ext 292 & 257



www.doj.gov.in/



सत्यमेव जयते

Department of Justice
Ministry of Law and Justice
Government of India

विधिक साक्षरता एवं

विधिक जागरूकता कार्यक्रम 2021-2023

न्याय तक सार्वभौमिक पहुंच



श्री अर्जुन राम मेघवाल

माननीय राज्य मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार)

अनुच्छेद 39ए

सभी के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना

एसडीजी 16

सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना

न्याय विभाग की यात्रा का दशक कानूनी अधिकारिता की ओर

A2J-UNDP परियोजना (2009 - 2012)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से सीमांत लोगों के लिए न्याय तक पहुंच

भौगोलिक विस्तार

बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

A2J-NEJK प्रोजेक्ट (2012 - 2017)

- विचाराधीन कैदियों सहित गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना
- गांव आधारित कानूनी क्लिनिक स्थापित करने में विधि महाविद्यालयों/एलएसए के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करना
- सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना

भौगोलिक विस्तार

असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख

पहले चरण की उपलब्धियां

20,672+

पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाया गया

1,400

गाँव बुरास और बूढ़ी औपचारिक न्याय संरचना के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संवेदनशील बने

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में एसआईआरडी के साथ सहयोग करना

15500+

कानूनी जागरूकता अभियान और संवेदीकरण अभियान आयोजित किए गए

दूसरे चरण की उपलब्धियां

7.12 लाख

लाभार्थियों को कवर किया गया

1,884

ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाया गया

4390

कानूनी साक्षरता/कानूनी जागरूकता अभियान आयोजित किए गए

8.3 लाख

26 भाषाओं में 69 कानूनों पर आईईसी सामग्री

20,000+

मास्टर ट्रेनर्स

158

सामुदायिक स्तर पर कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित करना



अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए 2021-2023 के दौरान 14 एजेंसियों को शामिल किया गया है।

सरकार/स्वायत्त/अनुसंधान निकाय

अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

परियोजना: 'परंपरागत ग्राम परिषद प्रणाली की प्रथाओं और भारत के औपचारिक कानूनों के बीच तालमेल'

महत्वपूर्ण पहल:

- 1367 गाँव बुराह और गाँव बूढ़ी को संवेदनशील बनाया गया
- EIT10 अभियान: प्रत्येक को 10 और प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया

आउटरीच: 6,666

Website : www.nalsa.gov.in/dashboard/AR



सिक्किम राज्य महिला आयोग

परियोजना: 'महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों पर क्षमतावर्धन'

महत्वपूर्ण पहल:

- प्रासंगिक सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर टॉक शो।
- महिलाओं से संबंधित कानूनों पर हितधारकों की कानूनी जागरूकता

आउटरीच: 1,17,956

Website : www.sikkim.gov.in/



जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर

परियोजना: 'बाल यौन शोषण के खिलाफ हितधारकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण'

महत्वपूर्ण पहल:

- संवेदीकरण कार्यशालाएं और प्रशिक्षण मॉड्यूल
- प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण के उपाय
- पीड़ितों और उनके परिवारों को मनोसामाजिक सहायता

आउटरीच: 2,605

Website : www.jnims.nic.in/



लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी, असम

परियोजना: 'पूर्वोत्तर राज्यों की पारंपरिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण'

महत्वपूर्ण पहल:

- जीवंत संस्कृति और जनजातियों के प्रथागत कानूनों की अनूठी विशेषताओं का दस्तावेजीकरण

आउटरीच: 204

Website : www.ghconline.gov.in/lri/



भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

परियोजना: 'कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन'

महत्वपूर्ण पहल:

- डाटा बैंक का डिजिटल भंडार विकसित करना
- आउटपुट और परिणामों के लिए डैशबोर्ड विकसित करें

Website : www.iipa.org.in/cms/public/



नागरिक सामाजिक संगठन/निजी निकाय

सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी (CECOEDECON), जयपुर, राजस्थान

परियोजना: 'महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना'

महत्वपूर्ण पहल:

- क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करना
- अग्रिम पंक्ति के स्वयंसेवकों की क्षमता निर्माण

आउटरीच: 58,898

Website : www.cecoedecon.org.in/



छाया विज्ञापन और संचार प्रा. लिमिटेड, भुवनेश्वर

परियोजना: 'डिजिटल लीगल लिटरेसी और सामुदायिक कानूनी जागरूकता'

महत्वपूर्ण पहल:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नुवकड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाएं
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आउटरीच: 7,105

Website : www.shadowadd.com



राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों

एनएलयू, नई दिल्ली

परियोजना: 'अधिकारों का ज्ञान उन्नति की पहचान'

महत्वपूर्ण पहल:

- महिला के विरुद्ध कूरता के मामलों में कानूनी निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना
- सामुदायिक भागीदारी का हाइपर-लोकल ग्रासरूट मॉडल तैयार करें

आउटरीच: 904

Website : www.nludelhi.ac.in/home.aspx



एनएलआईयू, भोपाल

परियोजना: 'राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल कानूनी साक्षरता - डिजाइन, विकास, प्रबंधन और परीक्षण - ई न्यायगंगा'

महत्वपूर्ण पहल:

- डिजिटल कानूनी साक्षरता पर डिजिटल आईईसी सामग्री का विकास और प्रबंधन
- डिजिटल सामग्री के निर्माण की सुविधा के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और निजी लॉ कॉलेजों के साथ 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए

आउटरीच: 3,705

Website : www.nliu.ac.in/

